सेबा में :प्रधान मंत्री,भारत सरकार, नयी दिल्ली, भारत।

बिषय:तिरहुत या मिथिला स्टेट इकनोमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए।

उत्तर बिहार (मिथिला) के बाढ़ समस्या का निदान सम्भब है यदि डॉ. के एल राव के " इंटरलिंकिंग आफ रिवर प्रोजेक्ट" को इम्प्लीमेंट किया जाय।

आज का बिहार, प्राचीन समय के मगध ,अंग , तिरहुत और काशी जनपद का हिस्सा है। बिहार ही नहीं पुरे देश को दुबारा, सिटी स्टेट्स में रीओर्गनइजे करने की आबश्यकता है, तभी सभी इलाके का विकास होगा और लोकल जन-आकांशा की पूर्ति भी।

तिरहुत स्टेट इकनोमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तिरहुत का नंबर एक प्रॉब्लम है बाढ़। कांग्रेस पार्टी से लेकर जनता दल /बीजेप की संयुक्त सरकार ने अबतक धोखा किया है। हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए ताकि तिरहुत industrialize हो सके। एक बार बाढ़ नियंत्रण हो जाय तो हमारा छेत्र अपनेआप इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बन जायेगा। डॉ के एल राव, १९५०-७० दशक के, विश्व के जाने-माने डेम इंजीनियर थे। नेहरू जी ने बाढ़- नियंत्रण के लिए (और सुखाड़ को रोकने के लिए) उन्हें सिचाई मंत्री बनाया था और एक प्लान बनाने को कहा था। १९७० के दशक में श्रीमती गाँधी को वो प्लान बनाकर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गाँधी को सौंपा था । उसे "Interlinking of Rivers" के नाम से जाना जाता है। इस प्लान के अनुसार नेपाल और भारत को मिलकर, नेपाल के प्रमुख नदियों पर डैम बनाना था । फिर अंडरग्राउंड नदियों और बृहत् नहर-तंत्र के द्वारा, जल को मध्य और दक्छिन भारत के नदियों के साथ जोड़ना था ।इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन नेपाल को देना है और लागत भारत को । इस बृहत् इन्वेस्टमेंट को भारत सरकार करना नहीं चाहती है और १९७० से बहानेबजी बनाती आ रही है, जैसे की कभी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की जाँच और पता नहीं अन्य कितने झूठे बहाने। बिहार बासियों को चुप रहने के लिए अलबत्ता कुछ दाने ऐड के रूप में मिल जाते हैं। ना तो उत्तर बिहारियों को इससे होनेबले नुकशान का अंदाजा है और न ही पटना स्थित मगहिया सरकार को। मगहिया क्यों चिंतित हो यदि उत्तर बिहार बाढ़ में हर साल डूबे। बलि उसे तो लाभ है कि बाढ़ -नियंत्रण के नाम पर जो केंद्र सरकार से बजट आता है, उसका बंदर-बाँट करके खा जाय। यही १९६० से बिहार सरकार का रिकॉर्ड है।

भारत में एक तरफ सुखार के चलते किसान आत्म हत्या कर रहे हैं, और दूसरे तरफ पूर्वी राज्यों का जीवन हर साल अस्त-ब्यस्त हो जाता है। सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है; घर-मबेशी बा ढ़ में बाह जाते हैं। हमें अपना उत्तर बिहार स्टेट चाहिए , ताकि हमारा मुख्या मंत्री, केंद्र सरकार और नेपाल सरकार के साथ मिलकर, साथ ही दूसरे राज्यों के साथ मिलकर, उत्तर बिहार को बाढ़-मुक्त और इन्वेस्टमेंट के लायक बना सके।

स्टेट बनाने का पूरा पावर प्रधान मंत्री (लोक सभा/राज्य सभा) को है, राज्य सरकार चाह कर भी इसे रोक नहीं सकती। रोकने का क़ानूनी अधिकार उसके पास नहीं है, क्योंकि यह केंद्र का बिसय (central subject Art 3 of Indian Constitution) है। प्रधान मंत्री यदि चाहें, तो २०२५ में मिथिला एक पृथक राज्य बन सकता है।

प्रधानमंत्री जी,जन -आकांक्षा है कि देश को छोटे-छोटे इकनोमिक स्टेट्स में (प्राचीन सभी जनपद और अन्य) सुनियोजित किया जाय। पूरे राष्ट्र की राज -काज की भाषा English, हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत भी हो। निवेदन है की यथाशीघ्र इसे पूरा करें।

अमरनाथ झा "बक्शी "
लॉरेन्सविल, न्यू जर्सी , यू एस ए।
फरबरी २१ , २०२५।